वस्त्र मंत्रालय

जनवरी , 2019 के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और उपलब्धियाँ

1. नीतिगत निर्णय :

i. पावर टैक्स इण्डिया के लिए 2017-18 से 2019-20 का एसएफसी परिव्यय 487. 07 करोड़ रुपये है। अब, पावरटैक्स इंडिया और निटवेअर सेक्टर के लिए 2017-18 से 2019-20 के लिए 487.07 करोड़ रुपये के परिव्यय से संयुक्त एसएफसी प्रस्ताव का 15.01.2019 को सचिव (वस्त्र) द्वारा मूल्यांकन किया गया था व 30.01.2019 को माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा इसको अनुमोदित किया गया था।

2. महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ :

i. हथकरघा क्षेत्र:

(क) एमएसएमई सहायता और आउटरीच कार्यक्रम के तहत, 12 चिन्हित जिलों में संबंधित बुनकर सेवा केंद्रों के समन्वय से विभिन्न क्रियाकलाप किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ से, 88,779 पहचान कार्डों के लिए, 11766 कौशल उन्नयन/वर्कशेड/करघे/प्रकाश इकाइयों के लिए, 44310 यार्न पासबुक, 8045 मुद्रा ऋण के लिए, 10105 सामाजिक सुरक्षा (बीमा) के लिए बुनकरों का नामांकन किया गया है। हथकरघा मार्क/इंडिया हैंडलूम ब्रांड्स के लिए 113 पंजीकरण और 20420 हैंडलूम मार्क/आईएचबी लेबल जारी किए गए हैं। 9012 बुनकरों ने विपणन कार्यक्रमों में भाग लिया और इससे 578.13 करोड़ रु मूल्य की बिक्री हुई।

(ख) जनवरी, 2019 में चंडीगढ़, बैंगलुरु, हुबली और दिल्ली में चार राष्ट्रीय स्तर विशेष हथकरघा और बैंगलुरु में एक राज्य स्तरीय एक्सपो और सिल्क फैब कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें उपभोक्ता और हथकरघा बुनकरों के बीच प्रत्यक्ष विपणन इंटरफ़ेस प्रदान किया गया। विदेशी बाजार में हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए जनवरी 2019 के दौरान 03 अंतर्राष्ट्रीय मेले जैसे अंतर्राष्ट्रीय सोर्सिंग एक्सपो, जर्मनी और फ्रांस में आयोजित किये गये।

(ग) हथकरघा बुनकरों को 10000/- रुपए प्रति बुनकर की दर से बुनकर मुद्रा योजना के तहत मार्जिन राशि पर 6% रियायती ब्याज दर और 03 वर्ष की अवधि के लिए ऋण गारंटी पर ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, वर्ष 2015-16 से 30.11.2018 तक 1,37,891 मुद्रा ऋण स्वीकृत किए गए थे जिसके लिए स्वीकृत ऋण राशि 631.03 करोड़ रु थी, जिसमें से 527.85 करोड़ की राशि वितरित की गई थी। मात्र नवंबर 2018 में, 18.61 करोड़ रु की राशि के मूल्य 3863 मुद्रा ऋण स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से रु 19.42 करोड़ की राशि वितरित की गई थी।

ii. <u>हस्तशिल्प क्षेत्र:</u> माननीय प्रधान मंत्री ने 2 नवंबर, 2018 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए एक समर्थन और आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में, प्रधान मंत्री ने इस क्षेत्र की सुविधा के लिए पांच प्रमुख पहलुओं पर केन्द्रित 12 प्रमुख पहलें शुरू की थी। इनमें ऋण सुविधा, बाजार सुविधा, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यवसाय करने में आसानी और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा की भावना शामिल हैं। एमएसएमई समर्थन और आउटरीच कार्यक्रम का उद्देश्य एमएसएमई के लिए कार्यान्वयन योग्य बहुआयामी समाधान प्रदान करने हेतु विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, ऋणदाताओं और निजी क्षेत्र को एक साथ लाकर सरकार के प्रयासों को बल प्रदान करना है ताकि एमएसएमई के लिए ऐसे समाधान प्रदान किए जा सके जिनका कार्यान्वयन किया जा सकता है। एमसएमई सहायता और आउटरीच पोर्टल 100 जिलों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की स्थिति की गहन निगरानी करता है। 31 जनवरी, 2019 तक 13 राज्यों (19 जिलों) में डीसी (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा की गई की पहल से 1.03 लाख से अधिक कारीगरों को लाभ हुआ, 51,995 कारीगरों को कारीगर पहचान पत्र जारी करने के लिए पहचान पहल के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है तथा 28379 पहचान पत्र कार्ड वितरित किए गए हैं। मुद्रा ऋण के लिए 12095 आवेदन जुटाए गए, 539 कारीगरों को आधुनिक टूल किट प्रदान किए गए हैं और 5753 से अधिक कारीगरों ने विभिन्न विपणन कार्यक्रमों में भाग लिया है जिसमें 955.01 लाख रुपये की बिक्री हुई।

ii. **<u>रेशम क्षेत्र</u>** : भारतीय रेशम मार्क संगठन (एसएमओआई), नई दिल्ली ने टीटीएल वाराणसी के सहयोग से "15 वीं प्रवासी भारतीय दिवस" में भाग लिया जिसका आयोजन विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 21 और 23 जनवरी, 2019 के दौरान दीन दयाल हैंडीक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स, लालपुर, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में किया गया। एसएमओआई ने सिल्क मार्क सहित केंद्रीय रेशम बोर्ड सीएसबी के कार्यकलापोंको प्रदर्शित किया है। थीम पवेलियन ने कोकून, रेशम के धागे, वस्त्र के नमूने, सिल्क मार्क लेबल जैसे- हैंग टैग, सिलाई लेबल आदि की सभी चार किस्में प्रदर्शित कीं। इस आयोजन में 66 स्टॉल थे, जिनमें से 40 स्टाल वस्त्र के हैं। यूएसए, सिंगापुर, फ्रांस , नीदरलैंड, हांगकांग और अन्य देशों के आगंतुक सिल्क मार्क स्टाल पर गए और सीएसबी/एसएमओआई के प्रयासों की सराहना की।

iv. <u>कपास:</u> जनवरी, 2019 के महीने में बीज कपास (कपास) की अखिल भारतीय आवक 57.21 लाख गाँठें रही। इसमें से बीज कपास की 3.50 लाख गांठें भारतीय कपास निगम (एमएसपी) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत प्राप्त की गई।

v. **<u>विद्युतकरघा क्षेत्र:</u>** विद्युतकरघा कामगारों हेतु समूह बीमा योजना के अंतर्गत विभिन्न नोडल एजेंसियों द्वारा योजना के अंतर्गत जनवरी, 2019 के दौरान कुल 4,12,328 रु के प्रीमियम वाले भारत सरकार के हिस्से के साथ 2,516 विद्युतकरघा कामगारों को पंजीकृत किया गया था।

vi. **<u>प्रौद्योगिकी उन्नयन</u>**: जनवरी, 2019 के महीने के दौरान , 685.37 करोड़ रु की परियोजना लागत और तथा संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (ए-टीयूएफएस) के तहत 45.22 करोड़ रु की सब्सिडी की आवश्यकता के साथ 171 यूआईडी जारी किए गए हैं।

vii. भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री एम वेंकैया नायडू ने 06.01.2019 को नई दिल्ली में वस्त्र क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 17 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किए।